

FORM -I

(For Linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Rudraprayag

R. No. 82
Dated 27/08/2021

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's Letter No. 11-98-FC (pt.) 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other traditional Forest dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ('FRA', for short) on the Forest land proposed to be divert for non-forest purpose read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that **0.4769** hectares of Forest land proposed to be diverted in favor of **Indian Railways** for **"Development of 126 km long broad Gauge New Rail Link between Rishikesh and Karanprayag in state of Uttarakhand"** which falls within jurisdiction of Village Nagrasu in Rudraprayag Teshil.

H/
30/6/21
PM
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.4769** Hectares of Forest area proposed of diversion, a copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s), Gram Sabha (s), Sub-divisional level committee (s) and the district level committee are enclosed annexure
- The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Group and pre-agricultural communities

Encl.: As above

H/
District Collector
रुद्रप्रयाग

Office of the District Collector Rudraprayag

District-Rudraprayag (Uttarakhand)

Proceedings of meeting of District Level Committee constituted under Schedule Tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA),2006.

A meeting of the District level Committee of District Rudrapryag (Uttarakhand) District Magistrate, Rudraprayag on date 27/8/21..... at Rudraprayag in which the application claiming rights in villages Nagrasu in Rudraprayag teshil area measuring 0.4769 hectares for "Development of 126 km long broad Gauge New Rail Link between Rishikesh and Karanprayag in state of Uttarakhand" of forest land under FRA ,2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divisional level committee of Rudraprayag teshil were discussed to consider the same for admission by district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, no objections/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for said purpose.

Place:


Dated:



District Magistrate, Rudrapryag,



Chairman District Level Committee


Its is further certified that – Minutes of meetings of "Development of 126 km long broad Gauge New Rail Link between Rishikesh and Karanprayag in state of Uttarakhand" regarding FRA is as following:-

S.No		Remarks
(a)	For complete process for identification and settlement of right under FRA has been carried out for 0.4769 Hectares of Forest area proposed for diversion .A copy of record and consultations and meetings of forest rights Committee(s), Sub Division level Committee(s).	Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes And other Traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by Government as required under section3(2) of FRA have been completed .	Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes And other Traditional Forest Dwellers.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal groups and Pre-Agriculture Communities.	Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes And other Traditional Forest Dwellers


जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी
District Social Welfare Officer
Rudraprayag


शीला रावत
सदस्य जिला पंचायत
वार्ड नं० 17
जलपथ-रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)


Divisional Forest Officer
Rudraprayag Forest Division


(Mahuj Goyal)
District Collector (Rudraprayag)

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य में 126km कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई
ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण

कार्यालय उपजिलाधिकारी रुद्रप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
अनापत्ति प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति रुद्रप्रयाग

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 126km कि०मी०
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.4769 हे०
सिविल वन भूमि जो कि नगरासू ग्राम में स्थित हैं। भारतीय रेल के पक्ष में भारत सरकार का
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया
गया।

उक्त प्रकरण के विषय में उपजिलाधिकारी कार्यालय में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में
प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदिन सिविल वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने
हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत
आवेदित सिविल वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा
कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपखण्ड स्तरीय समिति के सभी सदस्यों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त सिविल वन भूमि में
किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है।

सर्वसम्मति से उपखण्ड रुद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि०मी०
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल परियोजना निर्माण हेतु 0.4769 हे० सिविल वन भूमि ग्राम
नगरासू में भारतीय रेल (परियोजना एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त
कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

for
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील - रुद्रप्रयाग
जनपद - रुद्रप्रयाग




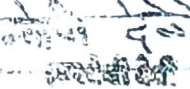
21/1/22
SDM
उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


for
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
उप जिलाधिकारी तहसील - रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग
जनपद - रुद्रप्रयाग

कार्यालय उपजिलाधिकारी रुद्रप्रयाग
उपखण्ड सतरीय समिति रुद्रप्रयाग

आज दिनांक ३६/८/२०१९ का उत्तराखण्ड राज्य में १२६ कि०मी० ऋषिकेश - कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम २००६ एवं नियम २००८ के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
१	श्री जय किशन (IAS)	उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष रुद्रप्रयाग	
२		उप प्रमाणीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग	
३	संजीव पाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	
४	अनन्ताजी देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र नगरासू	

रुद्र प्रयाग
पृष्ठ सं०-३३


(अस. सी० नै. वि०)
वन क्षेत्र अधिकारी
रुद्रप्रयाग रेज

परियोजना का नाम :- 126 km Long Broad Gauge Rail Link connecting Rishikesh - Kamprayag in the state of Uttarakhand

वन अधिकार अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नाशिराई
तहसील रूड़ जिला रूड़

उत्तराखण्ड में जनपद रूड़ के अन्तर्गत 126 km परियोजना के निर्माण हेतु (0.50 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.4769 हे० सिविल सोयम भूमि 0.00 हे० वन पंचायत भूमि 0.00 हे०) अर्थात् कुल 0.9769 वन भूमि का विभाग/संस्था के पास में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नाशिराई द्वारा दिनांक 24/7/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2008 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नाशिराई के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि मार्च 2008 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर /
ग्राम सचिव



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

ग्राम पंचायत नगरास

पंचायत समिति, पंचायत नगरपालिका
प्रमुख प्रधान द्वारा
दिनांक 25/7/2071
विषय अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग